Exam Genius

India's No. 1 Platform for UPSC | SSC | BANK RAILWAY Exam

BANKING AND FINANCIAL AWARENESS

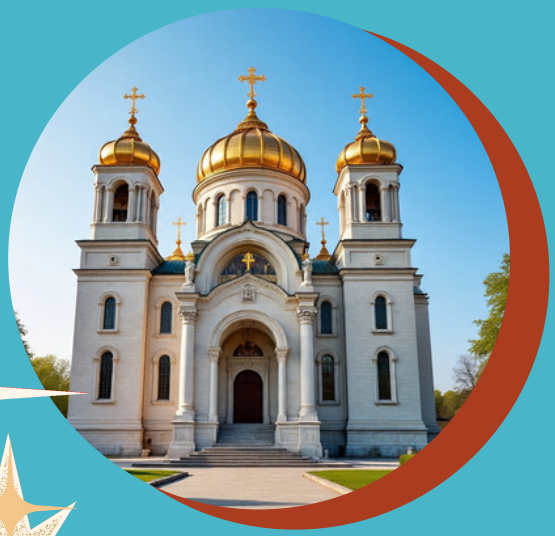

11 - 17 JAN 2026

2ND WEEK OF JANUARY

50+ MCQ with detailed explanation

- Banking & finance
- Banking Facilities
- Banking Appointment
- Banking Agreement

Ques: Which bank launched 'The Fortuna Wave' as its refreshed brand identity to signal modernization and future-readiness?
आधुनिकीकरण और भविष्य लिए के दर्शाने को तैयारी-'द फॉर्चुना वेव' नामक नया ब्रांड पहचान किस बैंक ने लॉन्च किया?

A) South Indian Bank / साउथ इंडियन बैंक
B) Federal Bank Limited / फेडरल बैंक लिमिटेड
C) Bandhan Bank / बंधन बैंक
D) Yes Bank / यस बैंक
E) IDFC First Bank / आईडीएफसी फर्स्ट बैंक

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• Federal Bank Limited launched 'The Fortuna Wave', a refreshed brand identity, in Mumbai in the presence of Vidya Balan, the bank's brand ambassador.
• फेडरल बैंक लिमिटेड ने मुंबई में बैंक की ब्रांड एंबेसडर विद्या बालन की उपस्थिति में 'द फॉर्चुना वेव' नामक नई ब्रांड पहचान लॉन्च की।
• The new identity reflects the bank's transformation from a locally trusted institution into a national player with a growing global presence.
• यह नई पहचान बैंक के एक स्थानीय रूप से विश्वसनीय संस्थान से राष्ट्रीय स्तर के और बढ़ती वैश्विक उपस्थिति वाले खिलाड़ी में परिवर्तन को दर्शाती है।

About Federal Bank :

- Established : 1931
- HQ : Kochi, Kerala
- MD & CEO : KVS Manian
- Tagline : Your Perfect Banking Partner

Ques: **Which public sector bank was the most penalised by RBI in FY25 by value?**
FY25 में RBI द्वारा मूल्य के आधार पर सबसे अधिक जुर्माना किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पर

लगाया गया?

A) Canara Bank / केनरा बैंक
B) Indian Bank / इंडियन बैंक
C) State Bank of India / स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
D) Bank of India / बैंक ऑफ इंडिया
E) Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• In FY25 / CY25, the Reserve Bank of India (RBI) imposed monetary penalties totaling about ₹8.78 crore on Public Sector Banks (PSBs) for regulatory and compliance violations.
• FY25 / CY25 में भारतीय रिज़र्व बैंक)RBI) ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों)PSBs) पर नियामक और अनुपालन उल्लंघनों के लिए कुल मिलाकर लगभग ₹8.78 करोड़ का जुर्माना लगाया।
• State Bank of India (SBI) was the most penalised PSB, with a penalty of ₹1.72 crore.
• स्टेट बैंक ऑफ इंडिया)SBI) पर ₹1.72 करोड़ का जुर्माना लगाया गया, जो सबसे अधिक था।
• The penalty on SBI was mainly due to non-compliance with Priority Sector Lending (PSL) norms and deposit account regulations.
• SBI पर जुर्माना मुख्य रूप से प्राथमिकता क्षेत्र ऋण)PSL) और जमा खाता नियमों के अनुपालन से जुड़ी कमियों के कारण लगाया गया।
• Other PSBs penalised include Canara Bank (₹1.63 crore), Indian Bank (₹1.61 crore), Bank of India (₹1 crore), and Union Bank of India, Indian Overseas Bank, Bank of Baroda, Bank of Maharashtra, and PNB (₹29.60 lakh to ₹63.60 lakh).
• अन्य दंडित बैंकों में केनरा बैंक)₹1.63 करोड़(, इंडियन बैंक)₹1.61 करोड़(, बैंक ऑफ इंडिया)₹1 करोड़(, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और PNB (₹29.60 लाख से ₹63.60 लाखहैं। शामिल (
• RBI imposes such penalties to ensure regulatory compliance and strengthen banking discipline.
• RBI ऐसे दंड नियामक अनुपालन सुनिश्चित करने और बैंकिंग अनुशासन मजबूत करने के लिए लगाता है।

Ques: Till which date is the Special Revival Campaign launched by LIC for reviving lapsed individual policies valid?

LIC द्वारा लैप्स हो चुकी व्यक्तिगत पॉलिसियों को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किया गया विशेष पुनरुद्धार अभियान किस तिथि तक मान्य है?

A) 31 December 2025
B) 31 March 2026
C) 2 March 2026
D) 30 June 2026
E) 1 January 2026

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• Life Insurance Corporation of India (LIC) has launched a Special Revival Campaign to revive lapsed individual policies.
• भारतीय जीवन बीमा निगम) LIC) ने लैप्स हो चुकी व्यक्तिगत पॉलिसियों को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष पुनरुद्धार अभियान शुरू किया है।
• The campaign is applicable from 1 January 2026 to 2 March 2026.
• यह अभियान 1 जनवरी 2026 से 2 मार्च 2026 तक लागू रहेगा।
• Policies can be revived within five years from the date of the first unpaid premium.
• पॉलिसियों को पहले बकाया प्रीमियम की तिथि से पाँच वर्षों के भीतर पुनर्जीवित किया जा सकता है।
• The maximum late fee concession allowed under the scheme is ₹5,000. For outstanding premium up to ₹1 lakh, a concession of up to ₹3,000 is provided.
• इस योजना के तहत लेट फीस पर अधिकतम ₹5,000 तक की छूट दी जाएगी।₹1 लाख तक के बकाया प्रीमियम पर ₹3,000 तक की छूट मिलेगी।
• For premium between ₹1,00,001 and ₹3 lakh, the concession is up to ₹4,000. For premium of ₹3,00,001 and above, concession up to ₹5,000 is available.
• ₹1,00,001 से ₹3 लाख के बीच प्रीमियम पर ₹4,000 तक की छूट दी जाएगी।₹3,00,001 या उससे अधिक प्रीमियम पर ₹5,000 तक की छूट उपलब्ध है।
• In micro-insurance plans, 100% concession on late fee will be given.
• माइक्रो-इंश्योरेंस योजनाओं में लेट फीस पर 100% छूट प्रदान की जाएगी।

Ques: Which private sector bank faced the highest monetary penalty by value in CY25?

CY25 में मूल्य के आधार पर सबसे अधिक मौद्रिक जुर्माना किस निजी क्षेत्र के बैंक पर लगाया गया?

A) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
B) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
C) Axis Bank / एक्सिस बैंक
D) Jammu & Kashmir Bank / जम्मू एंड कश्मीर बैंक
E) Yes Bank / यस बैंक

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• In FY25 / CY25, the Reserve Bank of India (RBI) imposed monetary penalties totalling about ₹16.28 crore on private sector banks for various regulatory and compliance violations.
• FY25 / CY25 में भारतीय रिज़र्व बैंक)RBI) ने विभिन्न विनियामक और अनुपालन उल्लंघनों के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों पर कुल लगभग ₹16.28 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया।
• Among all private sector banks, Jammu & Kashmir Bank faced the highest single monetary penalty by value.
• सभी निजी क्षेत्र के बैंकों में जम्मू एंड कश्मीर बैंक पर मूल्य के आधार पर सबसे अधिक एकल जुर्माना लगाया गया।
• The RBI imposed a penalty of ₹3.31 crore on Jammu & Kashmir Bank in March 2025.
• मार्च 2025 में RBI ने जम्मू एंड कश्मीर बैंक पर ₹3.31 करोड़ का जुर्माना लगाया।
• The violations included deficiencies in loan-related practices and non-compliance with customer protection norms.
• उल्लंघनों में ऋण से जुड़ी प्रक्रियाओं में कमी और ग्राहक संरक्षण मानदंडों का अनुपालन न करना शामिल था।
• Due to this, Jammu & Kashmir Bank emerged as the most penalised private sector bank by value in CY25.
• इसी कारण CY25 में जम्मू एंड कश्मीर बैंक मूल्य के आधार पर सबसे अधिक दंडित निजी क्षेत्र का बैंक बन गया।

Ques: Which regulator notified the phased rollout of revised net worth and liquid net worth requirements for existing Merchant Bankers through amendments to the 1992 regulations?

मर्चेंट बैंकरों के लिए 1992 के विनियमों में संशोधन कर संशोधित नेटवर्थ एवं लिक्विड नेटवर्थ आवश्यकताओं के चरणबद्ध क्रियान्वयन की अधिसूचना किस नियामक ने जारी की?

A) RBI / भारतीय रिज़र्व बैंक
B) SEBI / भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
C) IRDAI / बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण
D) PFRDA / पेंशन निधि विनियामक
E) MCA / कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• SEBI amended the SEBI (Merchant Bankers) Regulations, 1992, now called the SEBI (Merchant Bankers) (Amendment) Regulations, 2025.
• सेबी ने 1992 के मर्चेंट बैंकर विनियमों में संशोधन कर 2025 संशोधन विनियम लागू किए।
• Net worth requirement: Category-I ₹25 crore by 02 Jan 2027 and ₹50 crore by 02 Jan 2028; Category-II ₹7.5 crore by 02 Jan 2027 and ₹10 crore by 02 Jan 2028.
• नेटवर्थ आवश्यकता-श्रेणी :I ₹25 करोड़)02 जनवरी 2027) व ₹50 करोड़)02 जनवरी 2028); श्रेणी-II ₹7.5 करोड़)02 जनवरी 2027) व ₹10 करोड़)02 जनवरी 2028)।
• Liquid Net Worth (LNW): Category-I ₹6.25 crore (2027) and ₹12.5 crore (2028); Category-II ₹1.875 crore (2027) and ₹2.5 crore (2028).
• लिक्विड नेटवर्थ-श्रेणी :I ₹6.25 करोड़)2027) व ₹12.5 करोड़)2028); श्रेणी-II ₹1.875 करोड़)2027) व ₹2.5 करोड़)2028)।
• Underwriting limit capped at 20 times of LNW, defined as unencumbered liquid assets like cash, bank deposits, G-Secs and select MF units.
• अंडरराइटिंग सीमा LNW के 20 गुना तक, जिसमें नकद, बैंक जमा, सरकारी प्रतिभूतियाँ व चयनित म्यूचुअल फंड शामिल हैं।
• Minimum revenue over 3 years mandated: ₹25 crore (Category-I) and ₹5 crore (Category-II), failing which registration may be cancelled.
• 3 वर्षों में न्यूनतम राजस्व अनिवार्य :₹25 करोड़ -श्रेणी)I) व ₹5 करोड़ -श्रेणी)II), अन्यथा

पंजीकरण रद्द हो सकता है।
• Independent compliance officer to be appointed by 03 April 2026; principal officers need 5 years' market experience with one-year compliance window.
• 03 अप्रैल 2026 तक स्वतंत्र अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति; प्रिंसिपल ऑफिसर हेतु 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक।
• Core merchant banking activities cannot be outsourced and existing arrangements must be unwound by 03 April 2026.
• मुख्य मर्चेंट बैंकिंग गतिविधियों का आउटसोर्सिंग निषिद्ध, 03 अप्रैल 2026 तक मौजूदा व्यवस्थाएँ समाप्त करनी होंगी।
• MBs cannot manage issues where connected persons hold over 0.1% equity or shares exceeding ₹10 lakh (whichever is lower).
• जिन मामलों में संबंधित व्यक्तियों की हिस्सेदारी 0.1% या ₹10 लाख से (हो कम जो) हो अधिक, वहाँ इश्यू प्रबंधन प्रतिबंधित है।

Ques: Which State recorded the highest growth in own tax revenue (excluding Union taxes) during April–November FY26?
अप्रैल–नवंबर FY26 के दौरान केंद्र के करों के हिस्से को छोड़कर स्वयं के कर राजस्व में सबसे अधिक वृद्धि किस राज्य ने दर्ज की?

A) Gujarat / गुजरात
B) Maharashtra / महाराष्ट्र
C) Uttar Pradesh / उत्तर प्रदेश
D) Karnataka / कर्नाटक
E) Tamil Nadu / तमिलनाडु

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• As per data released by the Comptroller and Auditor General (C&AG), Karnataka recorded the highest growth rate in States' own tax revenue during April–November FY26, excluding the share of Union taxes.
• नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक)C&AG) के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल–नवंबर FY26 के दौरान केंद्र के करों के हिस्से को छोड़कर राज्यों के स्वयं के कर राजस्व में सबसे अधिक वृद्धि कर्नाटक ने दर्ज की।

• Karnataka was followed by Maharashtra and Uttar Pradesh in terms of growth rate, though in absolute tax collection Maharashtra and Uttar Pradesh remain ahead of Karnataka.
• कर राजस्व की वृद्धि दर में कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश रहे, हालांकि कुल कर संग्रह के वास्तविक आंकड़ों में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश अब भी कर्नाटक से आगे हैं।
• The growth in tax revenue was influenced by post-GST rate rationalisation, which particularly impacted SGST collections.
• कर राजस्व वृद्धि पर GST दरों के युक्तिकरण का प्रभाव पड़ा, जिससे विशेष रूप से SGST संग्रह प्रभावित हुआ।
• In capital expenditure (capex), Gujarat emerged as the leading State, followed by Maharashtra and Karnataka.
• पूंजीगत व्यय रहा पर शीर्ष गुजरात में मामले के (कैपेक्स), उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक रहे।
• Several States are increasing capital expenditure aggressively to strengthen infrastructure in line with the Centre's push, while keeping fiscal deficits within recommended limits.
• कई राज्य केंद्र की नीति के अनुरूप बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए आक्रामक रूप से कैपेक्स बढ़ा रहे हैं, जबकि राजकोषीय घाटा अनुशंसित सीमा के भीतर बना हुआ है।

Ques: Which bank integrated the RBI's Central Bank Digital Currency (Digital Rupee – e₹) into its online merchant payment platform SmartGateway?
किस बैंक ने RBI की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रुपया डिजिटल)– e₹) को अपने ऑनलाइन मर्चेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म SmartGateway में एकीकृत किया है?

A) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक
B) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
C) Axis Bank / एक्सिस बैंक
D) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
E) Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक

Answer: Option D

Explanation :

• HDFC Bank included the Digital Rupee (e₹), the Reserve Bank of India's (RBI) Central Bank Digital Currency (CBDC), into their online merchant payment platform, SmartGateway.
• एचडीएफसी बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की केंद्रीय डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) डिजिटल रुपी (ई₹) को अपने ऑनलाइन मर्चेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म स्मार्टगेटवे में शामिल कर लिया है।
• It's As a result, in addition to current payment methods like UPI, cards, and net banking, SmartGateway merchants may now take payments using the Digital Rupee at no transaction fee.
• इसके परिणामस्वरूप, यूपीआई, कार्ड और नेट बैंकिंग जैसे मौजूदा भुगतान तरीकों के अलावा, स्मार्टगेटवे के व्यापारी अब बिना किसी लेनदेन शुल्क के डिजिटल रुपी का उपयोग करके भी भुगतान स्वीकार कर सकते हैं।

About HDFC Bank :

- Established : August 1994
- HQ : Mumbai
- MD & CEO : Sashidhar Jagdishan
- Tagline : We Understand Your World

Ques: Tamilnad Mercantile Bank (TMB) has partnered with which fintech company to strengthen its UPI acquiring and issuing capabilities?
तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक)TMB) ने अपनी UPI अधिग्रहण और जारी करने की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए किस फिनटेक कंपनी के साथ साझेदारी की है?

A) TechFini / टेकफिनी
B) Razorpay / रेज़रपे
C) PayU / पेयू
D) PhonePe / फोनपे
E) NPCI / एनपीसीआई

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

• Tamilnad Mercantile Bank has entered into a strategic partnership with TechFini to enhance its UPI acquiring and issuing capabilities.
• तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक ने अपनी UPI अधिग्रहण और जारी करने की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए टेकफिनी के साथ रणनीतिक साझेदारी की है।
• Under the collaboration, TechFini will act as the Technology Service Provider for TMB and manage UPI switching through its TechFini UPI Switch.
• इस सहयोग के तहत, टेकफिनी TMB के लिए टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर के रूप में कार्य करेगा और अपने TechFini UPI स्विच के माध्यम से UPI स्विचिंग का प्रबंधन करेगा।

Ques: Who has been appointed as the Chief Executive Officer (CEO) of HSBC Private Bank?
HSBC प्राइवेट बैंक की मुख्य कार्यकारी अधिकारी)CEO) के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

A) Jane Fraser / जेन फ्रेजर
B) Ida Liu / आइडा लियू
C) Alison Rose / एलिसन रोज
D) Nuno Matos / नूनो माटोस
E) Georges Elhedery / जॉर्जेस एलहदरी

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• Ida Liu has been appointed as the Chief Executive Officer (CEO) of HSBC Private Bank.
• आइडा लियू को HSBC प्राइवेट बैंक की मुख्य कार्यकारी अधिकारी)CEO) नियुक्त किया गया है।
• Prior to joining HSBC, she served as the Global Head of Citi Private Bank since 2007.
• HSBC में शामिल होने से पहले, वह 2007 से सिटी प्राइवेट बैंक की ग्लोबल हेड के रूप में कार्यरत थीं।
• HSBC Private Bank is headquartered in Geneva, Switzerland, and its Chairman is Peter Widmer.

• HSBC प्राइवेट बैंक का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है और इसके चेयरमैन पीटर विडमर हैं।

Ques: What is the maximum dividend payout cap proposed for commercial banks, small finance banks and payments banks under the revised framework?
संशोधित ढांचे के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंकों और पेमेंट्स बैंकों के लिए अधिकतम लाभांश वितरण सीमा क्या प्रस्तावित की गई है?

A) 60% of net profit / शुद्ध लाभ का 60%
B) 70% of net profit / शुद्ध लाभ का 70%
C) 75% of net profit / शुद्ध लाभ का 75%
D) 80% of net profit / शुद्ध लाभ का 80%
E) No upper limit / कोई ऊपरी सीमा नहीं

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• Under the proposed framework, dividend payouts are capped at 75% of net profit for commercial banks, small finance banks and payments banks.
• प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंकों और पेमेंट्स बैंकों के लिए लाभांश वितरण की सीमा शुद्ध लाभ के 75% तक निर्धारित की गई है।
• Regional rural banks and local area banks will be allowed to distribute dividends up to 80% of net profit.
• क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लोकल एरिया बैंकों को शुद्ध लाभ का 80% तक लाभांश वितरित करने की अनुमति होगी।
• Banks incorporated in India must report positive adjusted profit after tax for the relevant period to be eligible for dividend payout.
• भारत में स्थापित बैंकों को पात्र होने के लिए संबंधित अवधि में सकारात्मक समायोजित कर पश्चात लाभ दिखाना अनिवार्य होगा।
• Foreign banks operating through branches must have positive profit after tax from Indian operations to remit earnings to their head offices.
• शाखा मोड में कार्यरत विदेशी बैंकों को अपने मुख्यालय को लाभ भेजने के लिए भारतीय परिचालन से कर पश्चात सकारात्मक लाभ होना आवश्यक है।

• The proposed directions apply to commercial banks, small finance banks, payments banks, regional rural banks and local area banks.
• ये प्रस्तावित दिशानिर्देश वाणिज्यिक बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट्स बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और लोकल एरिया बैंकों पर लागू होंगे।
• The revised directions also cover all commercial banks, including State Bank of India and foreign banks operating in India through branches.
• संशोधित दिशानिर्देश भारतीय स्टेट बैंक सहित सभी वाणिज्यिक बैंकों और भारत में शाखा के माध्यम से कार्यरत विदेशी बैंकों पर लागू होंगे।
• Eligible foreign banks can remit profits to their head offices without prior RBI approval, subject to audited accounts and continued compliance with capital requirements.
• पात्र विदेशी बैंक, खातों के ऑडिट और पूंजी आवश्यकताओं के अनुपालन की शर्त पर, RBI की पूर्व अनुमति के बिना अपने मुख्यालय को लाभ प्रेषित कर सकेंगे।

Ques: What is the purpose of the Supervisory Data Quality Index (sDQI) created by the Reserve Bank of India?
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए सुपरवाइजरी डेटा क्वालिटी इंडेक्स)sDQI) का उद्देश्य क्या है?

A) To assess profitability of banks / बैंकों की लाभप्रदता का आकलन
B) To measure data quality in regulatory returns / नियामकीय रिटर्न में डेटा गुणवत्ता का मापन
C) To rank banks based on customer service / ग्राहक सेवा के आधार पर बैंकों की रैंकिंग
D) To evaluate credit growth / ऋण वृद्धि का मूल्यांकन
E) To monitor monetary transmission / मौद्रिक संचरण की निगरानी

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• The Reserve Bank of India (RBI) has created the Supervisory Data Quality Index (sDQI) to measure the quality of data submitted by banks.
• भारतीय रिज़र्व बैंक)RBI) ने बैंकों द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा की गुणवत्ता को मापने के लिए सुपरवाइजरी डेटा क्वालिटी इंडेक्स)sDQI) बनाया है।

• The index evaluates data quality based on accuracy, timeliness, completeness and consistency in submission of regulatory returns.
• यह सूचकांक नियामकीय रिटर्न के प्रस्तुतिकरण में सटीकता, समयबद्धता, पूर्णता और निरंतरता के आधार पर डेटा गुणवत्ता का मूल्यांकन करता है।
• RBI reported that the sDQI score of Scheduled Commercial Banks improved to 90.7 in the September 2025 quarter from 89.9 in April–June 2025.
• RBI के अनुसार, सितंबर 2025 तिमाही में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का sDQI स्कोर अप्रैल–जून 2025 की 89.9 से बढ़कर 90.7 हो गया।
• Among bank groups, Small Finance Banks recorded the highest sDQI score of 91.5, followed by Public Sector Banks at 91.1.
• बैंक समूहों में स्मॉल फाइनेंस बैंकों का sDQI स्कोर सबसे अधिक 91.5 रहा, इसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 91.1 रहा।
• Private Sector Banks (90.6) and Foreign Banks (90.4) also remained in the "good" category.
• निजी क्षेत्र के बैंक)90.6) और विदेशी बैंक)90.4) भी "अच्छी" श्रेणी में रहे।
• In September 2025, no Scheduled Commercial Bank scored below 80, indicating overall improvement in data quality.
• सितंबर 2025 में किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का स्कोर 80 से नीचे नहीं रहा, जो डेटा गुणवत्ता में समग्र सुधार को दर्शाता है।
• As per sDQI grading: less than 70 indicates "major concerns", 70–80 "needs improvement", 80–90 "acceptable", and above 90 "good".
• sDQI ग्रेडिंग के अनुसार :70 से कम "गंभीर चिंता", 70–80 "सुधार आवश्यक", 80–90 "स्वीकार्य" और 90 से अधिक "अच्छा" दर्शाता है।
• The sDQI currently covers 87 Scheduled Commercial Banks and assesses returns related to asset quality, liquidity, risk-based supervision, and capital adequacy.
• sDQI वर्तमान में 87 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को कवर करता है और परिसंपत्ति गुणवत्ता, तरलता, जोखिम का रिटर्न संबंधित से पर्याप्तता पूंजी और पर्यवेक्षण आधारित- है। करता मूल्यांकन

Ques: Which bank has introduced the 'Safety Centre' feature on its mobile banking app to enhance protection against digital fraud?
डिजिटल धोखाधड़ी से सुरक्षा बढ़ाने के लिए 'Safety Centre' फीचर किस बैंक ने अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप पर शुरू किया है?

A) State Bank of India / स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

B) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
C) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
D) Axis Bank / एक्सिस बैंक
E) Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• Axis Bank has introduced a new feature called 'Safety Centre' on its mobile banking app to strengthen customer protection against digital fraud.
• एक्सिस बैंक ने डिजिटल धोखाधड़ी से ग्राहकों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप पर 'Safety Centre' नामक नया फीचर शुरू किया है।
• The initiative aims to provide customers with greater control over digital banking security and fraud prevention.
• इस पहल का उद्देश्य ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा और धोखाधड़ी रोकथाम पर अधिक नियंत्रण प्रदान करना है।

About Axis Bank :

- Established : 1993
- HQ : Mumbai, Maharashtra
- Chairman : Rakesh Makhija
- MD & CEO : Amitabh Chaudhary
- Tagline : Badhti Ka naam Zindagi

Ques: How many Non-Banking Financial Companies (NBFCs) had their Certificate of Registration (CoR) cancelled by the RBI during December 2025, including voluntary surrenders?
दिसंबर 2025 के दौरान RBI द्वारा कितन (सहित समर्पण स्वैच्छिक)ी नॉन बैंकिंग-) कंपनियों फाइनेंशियलNBFCs) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया?

A) 35
B) 45
C) 50
D) 51

E) 55

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• The Reserve Bank of India (RBI) cancelled the Certificate of Registration (CoR) of 35 NBFCs for non-compliance with regulatory requirements.
• भारतीय रिज़र्व बैंक)RBI) ने नियामकीय आवश्यकताओं का पालन न करने पर 35 NBFCs का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया।
• These cancellations were effective between December 9 and December 31, 2025.
• ये रद्दीकरण 9 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 के बीच प्रभावी हुए।
• Additionally, 16 NBFCs voluntarily surrendered their CoR to the RBI. This brought the total number of cancelled registrations to 51 NBFCs.
• इसके अतिरिक्त, 16 NBFCs ने स्वेच्छा से अपना CoR RBI को सौंप दिया। इससे कुल रद्द पंजीकरणों की संख्या 51 NBFCs हो गई।
• RBI exercised its powers under Section 45-IA(6) of the RBI Act, 1934.
• RBI ने यह कार्रवाई RBI अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA(6) के अंतर्गत की।

Ques: Which entity launched the 'Axis Finance Vyapar Business Loan', a collateral-free credit solution for Micro and Small Enterprises (MSEs) in India?
'एक्सिस फाइनेंस व्यापार बिजनेस लोन', जो सूक्ष्म और लघु उद्यमों)MSEs) के लिए एक बिना गारंटी ऋण समाधान है, किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया?

A) Axis Bank Limited / एक्सिस बैंक लिमिटेड
B) Axis Finance Limited / एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड
C) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक
D) SIDBI / सिडबी
E) NABARD / नाबार्ड

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• Axis Finance Limited (AFL), a wholly owned subsidiary of Axis Bank Limited, launched the 'Axis Finance Vyapar Business Loan'.
• एक्सिस बैंक लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड)AFL) ने 'एक्सिस फाइनेंस व्यापार बिजनेस लोन' लॉन्च किया।
• The loan is a collateral-free credit solution designed for Micro and Small Enterprises (MSEs) across semi-urban and rural markets in India.
• यह ऋण भारत के अर्धक् ग्रामीण और शहरी-षेत्रों में सूक्ष्म और लघु उद्यमों)MSEs) के लिए एक बिना गारंटी का ऋण समाधान है।
• The product offers collateral-free loans up to Rs 10 lakh with flexible repayment tenures.
• इस योजना के तहत 10 लाख रुपये तक का बिना गारंटी ऋण और लचीली पुनर्भुगतान अवधि प्रदान की जाती है।
• In addition, Axis Bank also launched the Safety Centre on its mobile banking application to enhance digital banking security for customers.
• इसके अलावा, एक्सिस बैंक ने अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप पर ग्राहकों की डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी सेंटर भी लॉन्च किया।

Ques: What is the purpose of the Capital Gains Account Scheme (CGAS) authorised by the Government of India?
भारत सरकार द्वारा अधिकृत कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम)CGAS) का उद्देश्य क्या है?

A) To provide short-term loans to taxpayers / करदाताओं को अल्पकालिक ऋण देना
B) To deposit unutilised long-term capital gains and claim tax exemption / अप्रयुक्त दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ जमा कर कर छूट का दावा करना
C) To promote savings among non-residents / अनिवासी भारतीयों में बचत को बढ़ावा देना
D) To invest capital gains directly in equity markets / पूंजीगत लाभ को सीधे इक्विटी बाजार में निवेश करना
E) To replace existing capital gains tax provisions / मौजूदा पूंजीगत लाभ कर प्रावधानों को प्रतिस्थापित करना

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• The Capital Gains Account Scheme (CGAS) is authorised by the Government of India to help taxpayers manage uninvested long-term capital gains or sale proceeds of specified capital assets.
• कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम)CGAS) भारत सरकार द्वारा अधिकृत योजना है, जो निर्दिष्ट पूंजीगत परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त अप्रयुक्त दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ को सुरक्षित रखने में सहायता करती है।
• The scheme allows taxpayers to deposit such uninvested amounts in a designated bank account.
• यह योजना करदाताओं को अप्रयुक्त राशि को एक विशेष बैंक खाते में जमा करने की अनुमति देती है।
• By depositing under CGAS, taxpayers can earn interest, claim tax exemption, and plan reinvestment for a period of up to three years.
• CGAS के अंतर्गत राशि जमा करने से करदाता ब्याज अर्जित कर सकते हैं, कर छूट का लाभ ले सकते हैं और तीन वर्ष तक पुनर्निवेश की योजना बना सकते हैं।
• From 1 January 2026, the scheme is applicable to Resident Individuals and Hindu Undivided Families (HUFs).
• 1 जनवरी 2026 से यह योजना निवासी व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों)HUFs) पर लागू होगी।
• CGAS accounts can be opened at ICICI Bank branches, excluding rural branches, as per the scheme rules.
• CGAS खाते ICICI बैंक की शाखाओं में खोले जा सकते हैं, लेकिन योजना के नियमों के अनुसार ग्रामीण शाखाएँ इसमें शामिल नहीं हैं।

Ques: According to the IRDAI Annual Report 2024–25, what does the rise in Unfair Business Practices (UFBP) grievances indicate in India's insurance sector?
IRDAI की वार्षिक रिपोर्ट 2024–25 के अनुसार, बीमा क्षेत्र में अनुचित व्यावसायिक प्रथाओं)UFBP) से संबंधित शिकायतों में वृद्धि क्या दर्शाती है?

A) Improvement in customer awareness / ग्राहकों की जागरूकता में सुधार
B) Decline in insurance penetration / बीमा पैठ में गिरावट
C) Rising concerns related to mis-selling / मिसबढ़त जुड़ी से सेलिंग-ी चिंताएँ
D) Reduction in total insurance policies / कुल बीमा पॉलिसियों में कमी
E) Increase in global insurance density / वैश्विक बीमा घनत्व में वृद्धि

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) released its Annual Report for 2024–25 highlighting trends in grievances, penetration, and density.
• भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण)IRDAI) ने 2024–25 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की, जिसमें शिकायतों, बीमा पैठ और घनत्व से जुड़े आंकड़े दिए गए हैं।
• Mis-selling refers to the sale of insurance products without proper disclosure of terms and conditions, product features, or suitability to customer needs.
• मिसशर्तों बिना बिक्री की उत्पादों बीमा है अर्थ का सेलिंग-, विशेषताओं या ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुरूपता की सही जानकारी दिए।
• Such practices lead to higher premiums, frequent policy lapses, and erosion of customer trust.
• इससे प्रीमियम का बोझ बढ़ता है, पॉलिसी लैप्स होती हैं और ग्राहकों का भरोसा कम होता है।
• Total grievances related to life insurers remained almost unchanged at 1,20,726 in 2023–24 and 1,20,429 in 2024–25.
• जीवन बीमा कंपनियों से जुड़ी कुल शिकायतें 2023–24 में 1,20,726 और 2024–25 में 1,20,429 रहीं, यानी लगभग स्थिर रहीं।
• However, UFBP-related grievances increased from 23,335 in 2023–24 to 26,667 in 2024–25.
• लेकिन अनुचित व्यावसायिक प्रथाओं से जुड़ी शिकायतें 2023–24 में 23,335 से बढ़कर 2024–25 में 26,667 हो गईं।
• The share of UFBP grievances rose from 19.33 percent in FY24 to 22.14 percent in FY25, indicating growing mis-selling concerns.
• कुल शिकायतों में UFBP की हिस्सेदारी FY24 में 19.33 प्रतिशत से बढ़कर FY25 में 22.14 प्रतिशत हो गई, जो मिसहै। दर्शाती को समस्या बढ़ती की सेलिंग-
• Insurance penetration in India stood at 3.7 percent in FY25, much lower than the global average of 7.3 percent.
• FY25 में भारत की बीमा पैठ 3.7 प्रतिशत रही, जो वैश्विक औसत 7.3 प्रतिशत से काफी कम है।
• Life insurance penetration declined from 2.8 percent in FY24 to 2.7 percent in FY25, while non-life insurance remained unchanged at 1 percent.
• जीवन बीमा पैठ FY24 में 2.8 प्रतिशत से घटकर FY25 में 2.7 प्रतिशत हो गई, जबकि नॉन-

बीमा लाइफ1 प्रतिशत पर स्थिर रहा।
• Insurance density increased marginally from 95 dollars in FY24 to 97 dollars in FY25, showing a gradual upward trend since 2016–17.
• बीमा घनत्व FY24 में 95 डॉलर से बढ़कर FY25 में 97 डॉलर हो गया, जो 2016–17 से निरंतर बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है।

Ques: Which company has received a ₹1,000 crore, 10-year ATM cash outsourcing contract from SBI?
SBI से ₹1,000 करोड़ का 10-वर्षीय ATM कैश आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी को मिला है?

A) Hitachi Payments / हिटाची पेमेंट्स
B) FIS Global / एफआईएस ग्लोबल
C) CMS Info Systems Ltd / CMS इंफो सिस्टम्स लिमिटेड
D) NCR Corporation / एनसीआर कॉर्पोरेशन
E) AGS Transact / एजीएस ट्रांजैक्ट

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• State Bank of India (SBI) has awarded a ₹1,000 crore, 10-year cash outsourcing contract to CMS Info Systems Ltd.
• भारतीय स्टेट बैंक)SBI) ने CMS Info Systems Ltd को ₹1,000 करोड़ का 10-वर्षीय कैश आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट दिया है।
• This is the first direct large cash outsourcing contract awarded by a PSU bank.
• यह किसी PSU बैंक द्वारा दिया गया पहला प्रत्यक्ष बड़ा कैश आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट है।
• The contract covers 5,000 SBI-owned ATMs across India, including managed services, improved cash efficiency, and higher ATM uptime.
• यह अनुबंध पूरे भारत में SBI के 5,000 स्वामित्व वाले ATM को कवर करता है, जिसमें मैनेज्ड सर्विसेज, बेहतर कैश दक्षता और उच्च ATM अपटाइम शामिल हैं।
• The contract is expected to go live this month.
• यह कॉन्ट्रैक्ट इसी महीने शुरू)go live) होने की उम्मीद है।
• CMS Info Systems is a leading player in ATM management and cash logistics services in India.
• CMS Info Systems भारत में ATM प्रबंधन और कैश लॉजिस्टिक्स सेवाओं की अग्रणी

कंपनी है।

Ques: According to the RBI's draft amendments, what is the minimum cooling-off period required for a director who has completed 10 years of continuous tenure on the board of a co-operative bank before being eligible for re-appointment to the same bank?
RBI के मसौदा संशोधनों के अनुसार, किसी सहकारी बैंक के बोर्ड में 10 वर्ष का निरंतर कार्यकाल पूरा करने वाले निदेशक को उसी बैंक में पुनर्नियुक्ति के लिए न्यूनतम कितना कूलिंग-होगा करना पूरा पीरियड ऑफ?

A) One year / एक वर्ष
B) Two years / दो वर्ष
C) Three years / तीन वर्ष
D) Five years / पाँच वर्ष
E) No cooling-off period / कोई कूलिंगनहीं अवधि ऑफ-

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• Under the draft amendments issued by the RBI, a director who has completed 10 years of continuous tenure on the board of a UCB, State Co-operative Bank, or Central Co-operative Bank will be eligible for re-appointment to the same bank only after a minimum cooling-off period of three years.
• RBI द्वारा जारी मसौदा संशोधनों के अनुसार, शहरी सहकारी बैंक)UCB), राज्य सहकारी बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंक के बोर्ड में 10 वर्षों का निरंतर कार्यकाल पूरा करने वाला निदेशक कम से कम तीन वर्ष के कूलिंग पात्र का पुनर्नियुक्ति में बैंक उसी ही बाद के पीरियड ऑफ-होगा।
• During this cooling-off period, the director cannot be associated with the bank in any capacity other than as a regular member or customer.
• इस कूलिंग अलावा के ग्राहक या सदस्य सामान्य से बैंक शकनिदे दौरान के अवधि ऑफ-सकता। रह नहीं जुड़ा में भूमिका भी किसी
• The restriction does not prevent such individuals from being appointed as directors on the board of another co-operative bank.

• यह प्रतिबंध ऐसे व्यक्ति को किसी अन्य सहकारी बैंक के बोर्ड में निदेशक बनने से नहीं रोकता।
• For calculating continuous tenure, the RBI will count the total time served on the boards of UCBs, State Co-operative Banks, and Central Co-operative Banks, including periods before any interruption of less than three years.
• निरंतर कार्यकाल की गणना के लिए RBI शहरी, राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंकों के बोर्ड में सेवा की कुल अवधि को शामिल करेगा, जिसमें तीन वर्ष से कम के अंतराल से पहले की अवधि भी जोड़ी जाएगी।
• However, periods of directorship preceding an interruption of at least three years will be excluded from the calculation.
• हालांकि, कम से कम तीन वर्षों के अंतराल से पहले की निदेशक अवधि को गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

Ques: Which public sector bank has received in-principle approval from the Reserve Bank of India (RBI) to set up a wholly-owned subsidiary for undertaking Standalone Primary Dealer (SPD) business?
भारतीय रिज़र्व बैंक)RBI) से स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर)SPD) व्यवसाय के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करने की सैद्धांतिक मंज़ूरी किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को मिली है?

A) Bank of Baroda / बैंक ऑफ बड़ौदा
B) Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक
C) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक
D) Canara Bank / केनरा बैंक
E) Union Bank of India / यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

• Bank of Baroda (BoB) has secured in-principle approval from the RBI to convert its existing Bank Primary Dealer (PD) authorization into a wholly-owned subsidiary for undertaking Standalone Primary Dealer (SPD) business.
• बैंक ऑफ बड़ौदा)BoB) को अपने मौजूदा बैंक प्राइमरी डीलर)PD) प्राधिकरण को स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर)SPD) के रूप में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में बदलने के

लिए RBI से सैद्धांतिक मंज़ूरी मिली है।
• Primary Dealers are authorised to buy and sell Government Securities (G-Secs), such as bonds and Treasury Bills (T-bills), directly from the RBI and resell them in the market.
• प्राइमरी डीलर्स को RBI से सीधे सरकारी प्रतिभूतियाँ)G-Secs) जैसे बॉन्ड और ट्रेज़री बिल)T-bills) खरीदने और बेचने की अनुमति होती है।
• In India, Primary Dealers are classified into two categories: Bank PDs and Standalone Primary Dealers (SPDs).
• भारत में प्राइमरी डीलर्स को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है बैंक :PDs और स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर्स)SPDs)।
• Bank PDs are specialised departments within existing commercial banks, while SPDs are subsidiaries of Scheduled Commercial Banks (SCBs).
• बैंक PDs मौजूदा वाणिज्यिक बैंकों के भीतर विशेष विभाग होते हैं, जबकि SPDs अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों)SCBs) की सहायक कंपनियाँ होती हैं।
• The RBI introduced the system of Primary Dealers in 1995 to strengthen the infrastructure of the Government Securities market.
• RBI ने सरकारी प्रतिभूति बाज़ार के बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने के लिए 1995 में प्राइमरी डीलर प्रणाली की शुरुआत की थी।
• Currently, there are 7 Standalone Primary Dealers (SPDs) and 14 bank-affiliated PDs operating in India.
• वर्तमान में भारत में 7 स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर्स)SPDs) और 14 बैंक प्राइमरी संबद्ध-हैं कार्यरत डीलर्स।
• RBI has increased the aggregate limit available to SPDs under the Standing Liquidity Facility at the existing repo rate from ₹10,000 crore to ₹15,000 crore, effective from 2 April 2025.
• RBI ने स्टैंडिंग लिक्विडिटी फैसिलिटी के तहत SPDs को उपलब्ध कुल सीमा को मौजूदा रेपो दर पर ₹10,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹15,000 करोड़ कर दिया है, जो 2 अप्रैल 2025 से प्रभावी है।

About Bank of Baroda :

- Established : 1908
- HQ : Vadodara, Gujarat
- Tagline : India's International Bank
- MD & CEO : Debadatta Chand

Ques: Which company has received a contract from India Post Payments Bank (IPPB) to launch a comprehensive digital investment platform for its customers across India?
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक)IPPB) से देशभर के ग्राहकों के लिए एक व्यापक डिजिटल निवेश प्लेटफॉर्म शुरू करने का अनुबंध किस कंपनी को मिला है?

A) Choice Wealth Private Limited / चॉइस वेल्थ प्राइवेट लिमिटेड
B) CAMS Investor Services / कैम्स इन्वेस्टर सर्विसेज
C) Karvy Fintech / कार्वी फिनटेक
D) Zerodha Broking Limited / ज़ेरोधा ब्रोकिंग लिमिटेड
E) HDFC Securities / एचडीएफसी सिक्योरिटीज

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

• Choice Wealth Private Limited has received a contract from India Post Payments Bank (IPPB) to launch a comprehensive digital investment platform.
• चॉइस वेल्थ प्राइवेट लिमिटेड को इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक)IPPB) से एक व्यापक डिजिटल निवेश प्लेटफॉर्म शुरू करने का अनुबंध मिला है।
• This platform will enable IPPB customers across the country to seamlessly access formal financial investment services.
• यह प्लेटफॉर्म IPPB के देशभर के ग्राहकों को औपचारिक वित्तीय निवेश सेवाओं तक सहज रूप से पहुँच प्रदान करेगा।
• India Post Payments Bank Limited (IPPB) was established in 2017.
• इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड)IPPB) की स्थापना 2017 में हुई थी।

About India Post Payments Bank Limited (IPPB):

- Established : 2017
- HQ : New Delhi, Delhi
- CEO & MD : R. Viswesvaran
- Tagline : Your Bank at Your Doorstep

Ques: Which company has received the Reserve Bank of India (RBI)'s approval to operate as both Payment Aggregator–Physical (PA-P) and Cross-

Border Payment Aggregator (PA-CB)?
भारतीय रिज़र्व बैंक)RBI) से पेमेंट एग्रीगेटर–फिजिकल)PA-P) और क्रॉस पेमेंट बॉर्डर-) एग्रीगेटरPA-CB) के रूप में संचालन की मंज़ूरी किस कंपनी को मिली है?

A) Paytm / पेटीएम
B) PhonePe / फोनपे
C) Razorpay / रेज़रपे
D) PayG / पेजी-
E) Cashfree / कैशफ्री

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• PayG has secured approval from the Reserve Bank of India (RBI) to operate as a Payment Aggregator–Physical (PA-P) and Cross-Border Payment Aggregator (PA-CB).
• पे) जी-PayG) को पेमेंट एग्रीगेटर–फिजिकल)PA-P) और क्रॉस) गेटरएग्री पेमेंट बॉर्डर-PA-CB) के रूप में संचालन के लिए RBI की मंज़ूरी मिली है।
• With this approval, PayG has completed its full suite of Payment Aggregator licences under the RBI regulatory framework.
• इस मंज़ूरी के साथ PayG ने RBI के नियामक ढांचे के अंतर्गत पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंसों का पूरा सेट प्राप्त कर लिया है।
• The company can now facilitate digital transactions across multiple modes such as online, offline (in-person), and cross-border use cases.
• कंपनी अब ऑनलाइन, ऑफलाइन में माध्यमों विभिन्न जैसे बॉर्डर-क्रॉस और (पर्सन-इन) है। सकती बना सक्षम को देन-लेन डिजिटल
• PayG was established in 2021 and is headquartered in Bengaluru, Karnataka.
• PayG की स्थापना 2021 में हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में स्थित है।

Ques: According to the First Advance Estimates (FAE) released by NSO, what is the projected real GDP growth rate of India for FY2025–26?
NSO द्वारा जारी प्रथम अग्रिम अनुमान)FAE) के अनुसार FY2025–26 के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है?

A) 6.5%
B) 6.8%
C) 7.0%
D) 7.4%
E) 8.0%

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• The National Statistics Office (NSO), under the Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI), released the First Advance Estimates (FAE) of GDP for FY2025–26 at constant (2011–12) and current prices.
• सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय)MoSPI) के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय)NSO) ने FY2025–26 के लिए GDP के प्रथम अग्रिम अनुमान)FAE) स्थिर)2011–12) और चालू मूल्यों पर जारी किए।
• As per the estimates, real GDP growth for FY26 is projected at 7.4%, higher than 6.5% recorded in FY25.
• अनुमान के अनुसार FY26 में वास्तविक GDP वृद्धि दर 7.4% रहने की संभावना है, जो FY25 के 6.5% से अधिक है।
• Real GDP at constant prices is estimated at ₹201.90 lakh crore in FY26, compared to ₹187.97 lakh crore in FY25.
• स्थिर मूल्यों पर वास्तविक GDP FY26 में ₹201.90 लाख करोड़ अनुमानित है, जबकि FY25 में यह ₹187.97 लाख करोड़ थी।
• Nominal GDP growth is estimated at 8% in FY26, lower than 10.4% in FY25, with nominal GDP at current prices pegged at ₹357.14 lakh crore in FY26, up from ₹330.68 lakh crore in FY25.
• नाममात्र GDP वृद्धि FY26 में 8% अनुमानित है, जो FY25 के 10.4% से कम है। चालू मूल्यों पर नाममात्र GDP FY26 में ₹357.14 लाख करोड़ रहने का अनुमान है, जो FY25 में ₹330.68 लाख करोड़ थी।
• Gross Value Added (GVA) at constant prices is estimated at ₹184.50 lakh crore in FY26, registering a growth of 7.3%.
• स्थिर मूल्यों पर सकल मूल्य वर्धन)GVA) FY26 में ₹184.50 लाख करोड़ अनुमानित है, जिसमें 7.3% की वृद्धि दर्ज की गई है।
• Nominal GVA is estimated at ₹323.48 lakh crore in FY26, growing by 7.7%, compared to ₹300.22 lakh crore in FY25.
• नाममात्र GVA FY26 में ₹323.48 लाख करोड़ अनुमानित है, जिसमें 7.7% की वृद्धि हुई है, जबकि FY25 में यह ₹300.22 लाख करोड़ था।

Ques: Which company recently launched 'PhonePe PG Bolt' for Visa and Mastercard transactions to provide secure and efficient in-app payments?
कौन सी कंपनी ने हाल ही में Visa और Mastercard लेन लिए के देन-'PhonePe PG Bolt' लॉन्च किया, जो इनहै बनाता प्रभावी और सुरक्षित को पेमेंट्स ऐप-?

A) Paytm / पेटीएम
B) PhonePe Payment Gateway (PhonePe PG) / फोनपे पेमेंट गेटवे
C) Razorpay / रेज़रपे
D) Cashfree / कैशफ्री
E) Google Pay / गूगल पे

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

• PhonePe Payment Gateway (PhonePe PG) has launched 'PhonePe PG Bolt' for Visa and Mastercard credit and debit card transactions.
• फोनपे पेमेंट गेटवे)PhonePe PG) ने Visa और Mastercard क्रेडिट और डेबिट कार्ड लेन-के देन लिए 'PhonePe PG Bolt' लॉन्च किया है।
• The solution uses device tokenization to provide a secure and efficient in-app checkout experience for PhonePe users and merchant partners.
• यह समाधान डिवाइस टोकनाइजेशन का उपयोग करता है ताकि PhonePe प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं और व्यापारी साझेदारों को सुरक्षित और प्रभावी इन अनुभव चेकआउट ऐप-सके। मिल
• By replacing sensitive card details with secure tokens, the system eliminates the need for CVV entry during subsequent transactions on the same device, simplifying the payment journey.
• संवेदनशील कार्ड विवरण को सुरक्षित टोकन से बदलकर, यह प्रणाली एक ही डिवाइस पर बाद के लेन में देन-CVV दर्ज करने की आवश्यकता को समाप्त करती है, जिससे भुगतान प्रक्रिया सरल बनती है।

About PhonePe:

- Established : 2015
- HQ : Bengaluru, Karnataka
- CEO : Sameer Nigam

Ques: Which bank won multiple awards including Best AI and ML Adoption, Best Fintech and DPI Adoption, and Best IT Risk Management at the 21st Annual Banking Technology Awards 2025?
21वें वार्षिक बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स 2025 में Best AI and ML Adoption, Best Fintech and DPI Adoption और Best IT Risk Management सहित कई पुरस्कार किस बैंक ने जीते?

A) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक
B) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
C) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
D) Bank of Baroda / बैंक ऑफ बड़ौदा
E) Axis Bank / एक्सिस बैंक

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

• Bank of Baroda emerged as the winner of multiple awards at the 21st Annual Banking Technology Awards 2025.
• 21वें वार्षिक बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स 2025 में बैंक ऑफ बड़ौदा ने कई पुरस्कार जीते।
• The bank won awards for Best AI and ML Adoption, Best Fintech and DPI Adoption, Best IT Risk Management, and Best Tech Talent.
• बैंक ने Best AI and ML Adoption, Best Fintech and DPI Adoption, Best IT Risk Management और Best Tech Talent के पुरस्कार प्राप्त किए।
• Bank of Baroda also received a Special Mention in the category of Best Technology Bank.
• बैंक ऑफ बड़ौदा को Best Technology Bank श्रेणी में विशेष उल्लेख)Special Mention) भी मिला।
• The awards were received by Dr Debadatta Chand, Managing Director and CEO, and Shri Sanjay V Mudaliar, Executive Director of Bank of Baroda.
• ये पुरस्कार बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक एवं CEO डॉ कार्यकारी और चंद देबदत्त . गए। किए प्राप्त द्वारा मुदलियार .वी संजय श्री निदेशक

Ques: What is the Ways and Means Advances (WMA) limit fixed by the RBI for the Government of the National Capital Territory of Delhi (GNCTD)?

भारतीय रिज़र्व बैंक)RBI) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली)GNCTD) सरकार के लिए Ways and Means Advances (WMA) की सीमा कितनी तय की है?

A) ₹750 crore
B) ₹820 crore
C) ₹890 crore
D) ₹950 crore
E) ₹1,000 crore

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

• The Reserve Bank of India (RBI) has fixed the Ways and Means Advances (WMA) limit for the Government of the National Capital Territory of Delhi (GNCTD) at ₹890 crore.
• भारतीय रिज़र्व बैंक)RBI) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली)GNCTD) सरकार के लिए Ways and Means Advances (WMA) की सीमा ₹890 करोड़ निर्धारित की है।
• The revised WMA limit is effective from January 09, 2026, and is meant to manage temporary mismatches in receipts and payments.
• संशोधित WMA सीमा 9 जनवरी 2026 से प्रभावी है और इसका उद्देश्य प्राप्तियों और भुगतानों में अस्थायी असंतुलन को संभालना है।
• With this revision, the aggregate WMA limit for all State Governments and Union Territories has increased to ₹61,008 crore from the earlier ₹60,118 crore.
• इस संशोधन के साथ सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए कुल WMA सीमा ₹60,118 करोड़ से बढ़कर ₹61,008 करोड़ हो गई है।
• The highest WMA limits among states are Uttar Pradesh (₹6,519 crore), Maharashtra (₹6,139 crore), and Tamil Nadu (₹4,582 crore).
• राज्यों में सबसे अधिक WMA सीमा उत्तर प्रदेश)₹6,519 करोड़(, महाराष्ट्र)₹6,139 करोड़) तमिलनाडु और (₹4,582 करोड़है। की (
• The interest rate on WMA is linked to the RBI repo rate, making it a policy-aligned liquidity management tool.
• WMA पर ब्याज दर RBI की रेपो दर से जुड़ी होती है, जिससे यह एक नीति तरलता संगत- है। बनता उपकरण प्रबंधन
• Overdrafts (OD) beyond the WMA limit attract an interest rate 2 percentage points above the repo rate.
• WMA सीमा से अधिक लिए गए ओवरड्राफ्ट)OD) पर रेपो दर से 2 प्रतिशत अंक अधिक

ब्याज लगता है।
• The repayment period for WMA is capped at 90 days, ensuring short-term liquidity management discipline.
• WMA की चुकौती अवधि अधिकतम 90 दिन है, जिससे अल्पकालिक तरलता प्रबंधन में अनुशासन बना रहता है।

Ques: What was India's retail inflation, measured by the Consumer Price Index (CPI), in December 2025, and what was the average CPI inflation for the year 2025?
दिसंबर 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति) CPI के अनुसारथी कितनी (, और 2025 में औसत CPI मुद्रास्फीति क्या रही?

A) 1.33% in December; 2.2% average in 2025 / दिसंबर में 1.33%; 2025 में औसत 2.2%
B) 2.5% in December; 3.0% average in 2025 / दिसंबर में 2.5%; 2025 में औसत 3.0%
C) 1.0% in December; 1.8% average in 2025 / दिसंबर में 1.0%; 2025 में औसत 1.8%
D) 1.8% in December; 2.5% average in 2025 / दिसंबर में 1.8%; 2025 में औसत 2.5%
E) 2.2% in December; 1.33% average in 2025 / दिसंबर में 2.2%; 2025 में औसत 1.33%

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

• India's retail inflation, measured by the Consumer Price Index (CPI), increased to 1.33% in December 2025, marking a three-month high.
• दिसंबर 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति)CPI के अनुसार (1.33% तक बढ़ गई, जो पिछले तीन महीनों में सबसे अधिक है।
• The average CPI-based inflation for the year 2025 was 2.2%, the lowest in 12 years.
• 2025 में औसत CPI आधारित मुद्रास्फीति 2.2% रही, जो पिछले 12 वर्षों में सबसे कम है।
• The data was released by the Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI).
• यह आंकड़ा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय)MoSPI) द्वारा जारी किया गया।